



**भारत सरकार**  
**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**  
**एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ**  
**Ministry of Environment, Forest & Climate Change**  
**Integrated Regional Office, Lucknow**



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
**Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696**  
**Email: roc.lko-mef@gov.in, goimoeffrolko@gmail.com**

पत्र संख्या 8बी/यू.पी./06/123/2020/एफ.सी. **1079**

दिनांक: 11.12.2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी,  
 17, राणा प्रताप मार्ग,  
 लखनऊ, उ०प्र०।

**Online Proposal No. FP/UP/Approach/48107/2020**

**विषय:** इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा बबेरु-कमासिन-राजापुर मार्ग, (एस०एच०-92) के किमी० नं०-2(चैनेज नं०-1.470 से 1.500) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं०-708, ग्राम-पल्हरी, तहसील-बाँदा, जिला-बाँदा में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.065348 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:** मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक सं०-1224/11-सी/FP/UP/Approach/48107/2020, दिनांक 24.11.2020

महोदय,

उपरोक्त मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक-664/11 सी/FP/UP/Approach/48107/2020 लखनऊ, दिनांक 22.09.2020 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी गयी थी।

प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 12.10.2020 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसकी उल्लिखित शर्तों की अनुपालना उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद बाँदा में बबेरु-कमासिन-राजापुर मार्ग, (एस०एच०-92) के किमी० नं०-2(चैनेज नं०-1.470 से 1.500) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं०-708, ग्राम-पल्हरी, तहसील-बाँदा, जिला-बाँदा में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.065348 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन की विधिवत स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 100 trees in (Ganchha forest block in Banda Range) at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.
3. The User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
4. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
5. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
6. No labour camp shall be established on the forest land.

7. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
8. The separator island will be provided in front of Fuel Station between acceleration and declaration lanes and the space shall be used for plantation and its boundary shall be demarcated by a 2 ft. wall.
- 9- Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station.
- 10- Greenery will be maintained by the user agency around the periphery of Retail outlet.
- 11-The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
12. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
13. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
14. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
15. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
16. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
17. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

भवदीया,

(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख सचिव(वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग), अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, बाँदा वन प्रभाग, बाँदा।
4. जिलाधिकारी, बाँदा।
5. वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा बिक्री), इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि0, प्रयागराज मण्डलीय कार्यालय, प्रयागराज।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली

  
(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)